खेत में सड़ने के लिए नहीं छोड़ते और उसे बेचने के लिए दर-दर नहीं भटकते। मेरी यह मांग है कि सरकार किसान हितैषी नीति बनाए और किसानों द्वारा उपजायी गयी फसल को उचित मूल्य पर खरीद कर भण्डारण करे।

Demand to provide housing and other facilities to Birhor tribes in the country

श्री बृजलाल खाबरी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, देश में विलुप्त प्राय जनजाति बिरहोर एवं अन्य जातियों के लोग बिना किसी आशियाने के अपनी जिन्दगी गुज़र-बसर करने को मजबूर हैं। सरकार उनके नाम पर करोड़ों प्रति वर्ष खर्च करती है, परन्तु उक्त जनजातियों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये लोग जंगलों में पेड़ के नीचे रहने को मजबूर हैं।

बिरहोर जनजाति की एक महिला, एतवरिया बिरहोर दिनांक 12.4.2010 को बुढ़मू झारखण्ड के जंगल में एक पेड़ के नीचे प्रसव पीड़ा से घंटों तक तड़पती रही और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसकी सहायता के लिए न तो आंगनवाड़ी केन्द्र एवं न ही उप-स्वास्थ्य केन्द्र से कोई आया, जब कि सरकार इन पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रही है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से, केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह कृपया देश में विलुप्त प्राय जनजाति बिरहोर एवं अन्य जातियों के लोगों को तुरन्त आशियाने सुनिश्चित कराए। जब तक सरकार आशियाना उपलब्ध नहीं करा पाती, तब तक सभी मूलभूत सुविधाओं सहित, आवश्यक चिकित्सा (प्रसव सुविधा आदि) उपलब्ध कराए जाने के निर्देश जारी करने का कष्ट करे।

Concern over misbehaviour and harassment of international passengers by private airlines at Hyderabad airport

श्री मोहम्मद अली खान (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, मैं इस हाउस का ध्यान हिन्दुस्तान के मुख़तलिफ़ शहरों, खास तौर से हैदराबाद से प्राइवेट एयरलायंस के जरिए दूसरे मुल्कों को जाने वाले मुसाफिरों की परेशानियों की तरफ दिलाना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के मुख़तलिफ़ राज्यों, खास तौर से आन्ध्र प्रदेश से बहुत से लोग नौकरी, तालीम, सैरो तफ़रीह वगैरा के मकसद से अपनी फैमिली के साथ दूसरे मुल्कों का सफर करते हैं। बाकायदा वीज़ा और दूसरे काग़जात होने के बावजूद प्राइवेट एयरलायंस, खास तौर से एमीरेट एयरलायंस का स्टाफ एयरपोर्ट पर मुसाफ़िरों को परेशान करता है। यहां तक कि बाकायदा वीज़ा और कन्फर्म्ड टिकट होने के बावजूद हिन्दुस्तानी मुसाफ़िरों को जहाज पर सवार होने के लिए बोर्डिंग पास न देने के वाक्यात भी सामने आए हैं। हाल ही में हैदराबाद के शम्साबाद एयरपोर्ट पर 20 मार्च, 2010 को भी एक ऐसा ही वाक्या पेश आया। एमीरेट एयरलायंस के स्टाफ ने हैदराबाद-दुबई-क़तर सैक्टर पर कन्फमर्ड टिकट रखने वाले मुसाफ़िरों को इम्मीग्रेशन सर्टिफिकेट और दूसरे कागजात के नाम पर परेशान किया तथा उन्हें न सिर्फ बोर्डिंग पास देने से इन्कार कर दिया, बल्कि धमकियां भी दीं। इससे उन मुसाफ़िरों को न सिर्फ ज़ेहानी परेशानी हुई, बल्कि उनके मुल्क के बाहर जाने के मक़सद में भी खलल पड़ा। इसलिए वज़ीर बराए सिविल एविएशन से मेरा मुतालिबा है कि वह इस मामले में मुदाख़लत करके हैदराबाद एयरपोर्ट पर एमीरेट एयरलायंस के मैनेजमेंट और अफ़सरान के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करें, ताकि आइन्दा इस किस्म के शर्मनाक वाक्यात को रोका जा सके।